

मंथन क्रमांक 67

भूत-प्रेत, तंत्र-मंत्र, जादू-टोना

कुछ मान्य सिद्धान्त है।

- 1 धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं वर्तमान समय में इन दोनों के बीच संतुलन बिगड़ गया है।
- 2 जो कुछ प्राचीन है वही सत्य है ऐसा अंध विश्वास ठीक नहीं। जो कुछ प्राचीन है वह पूरी तरह असत्य है ऐसी आधुनिकता भी ठीक नहीं। सत्य और असत्य का निर्णय विद्वानों को विचार मंथन के द्वारा करना चाहिये।
- 3 किसी भी यथार्थ को अंतिम सत्य कभी नहीं मानना और कहना चाहिये। प्रकृति में अंतिम सत्य होता ही नहीं। किसी विचार को अंतिम सत्य कहकर प्रचारित करने वाले बुरी नीयत के लोग होते हैं।
- 4 प्रकृति के रहस्य असीम हैं। पुराने रहस्यों पर विज्ञान पर्दा उठाता है तो नये रहस्य उसके सामने आ जाते हैं।
- 5 भारतीय मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति जितना गंभीर विचारक होता है वह उतना ही बड़ा नास्तिक होता है। विचारक पूजा पाठ अथवा भक्ति और उपासना की अपेक्षा चिंतन पर अधिक जोर देते हैं।
- 6 श्रद्धा और विचार बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ब्राम्हण प्रवृत्ति के लोग विचार प्रधान होते हैं तो अन्य तीन प्रवृत्तियों के लोग श्रद्धा प्रधान। दोनों व्यवस्था के लिये एक दूसरे के पूरक होने चाहिये।
- 7 विचार विहीन श्रद्धा व्यक्ति को मुर्खता की ओर बढ़ा सकती है तो श्रद्धा विहीन विचार धूर्तता की ओर।

मैं बचपन से ही आर्य समाज से जुड़ा रहा। प्रारंभ से ही मुझे स्वामी दयानंद के दो विचार याद रहे। 1 भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना अस्तित्व हीन समस्याएं हैं। 2 प्रत्येक व्यक्ति को सत्य को ग्रहण करने तथा असत्य को छोड़ने के लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये। इन दो बातों पर मैंने बचपन से ही बहुत विचार किया कि यदि कभी मुझे स्वामी दयानंद का कोई कथन सत्य से दूर प्रतीत हो तो मैं स्वामी जी के कथन को मानूँ अथवा अपने निष्कर्ष को। मैंने इस संबंध में बीच का मार्ग निकाला कि यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो मैं स्वामी जी के कथन को असत्य नहीं कहूँगा किन्तु उसे सत्य भी न मानकर अपने निष्कर्ष को सत्य मानूँगा। मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैंने बचपन में ही अष्टांग योग के माध्यम से बहुत आगे तक जाकर चिंतन मंथन में क्षमता प्राप्त की थी। यदि मैं 17 वर्ष की उम्र में ही राजनीति के कीचड़ में नहीं फंसा होता तो संभव है कि मेरी दिशा कुछ भिन्न होती।

बचपन में ही मुझे परिवार ने यह बताया कि भूत-प्रेत, तंत्र-मंत्र, जादू-टोना का अस्तित्व भी है और उसका प्रभाव भी होता है। आर्य समाज ने मुझे यह बताया कि ये सब अस्तित्वहीन हैं और इनका कोई प्रभाव नहीं होता। मैंने इस विषय में अनुसंधान शुरू किया मैं कई माह तक श्मसान में सोकर अनुभव करता रहा। अन्य भी कई प्रकार से मैंने सत्य को खोजने के प्रयास किये। 2004 तक के पचास वर्षों तक मेरे प्रयत्न जारी रहे। इस संबंध में मैंने कई घटनाओं को प्रत्यक्ष से देखा और स्वयं अनुभव भी किये। जब भी मुझे कहीं भूत-प्रेत होने की सूचना मिली तो मैं उस स्थान पर जाकर पूरी खोज करता रहा। न तो मुझे कभी श्मसान में भूत-प्रेत दिखा या अनुभव हुआ न ही किसी अन्य जगह पर। अधिकांश घटनाएँ किसी भ्रम या जालसाजी का परिणाम सिद्ध हुईं। मैंने सबके सामने ऐसी जालसाजियाँ सिद्ध भी करके बता दिया। मैं जब आपात काल में जेल में था तो मुझे एक जादूगर द्वारा कुछ जादू देखने को मिला। जेल में ही मैंने रिसर्च करके अपने साथियों को वे सारे खेल दिखा दिये। कई बार ऐसे भी अवसर आये, जब भूत-प्रेत पीडित व्यक्ति को मैंने मंत्र पढ़ने का बहाना बनाकर उस पर फूक दिया तो वह व्यक्ति ठीक हो गया। मैंने एक बार भूत-प्रेत का प्रभाव सिद्ध करने वालों को एक बहुत बड़ी राशि का इनाम देने की घोषणा की चुनौती दी। कई लोग आये। हजारों दर्शक एकत्रित हुए। झाड़-फूक वालों ने पूरा प्रयत्न किया। किन्तु सफल नहीं हुए। मैंने अपने शहर ही नहीं बल्कि आस पास के क्षेत्र तक भी किसी ऐसी जालसाजी टगी को सफल नहीं होने दिया जो भूत-प्रेत जादू-टोना तंत्र मंत्र के नाम पर फैलायी जा रही हो। सिर्फ हिन्दुओं तक ही नहीं बल्कि मुसलमानों आदिवासियों तक में मेरा विलक्षण प्रभाव था। आम तौर पर लोग ऐसे मामलों में मुझसे सम्पर्क करते रहे।

इन सबके बाद भी कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिन्हें मैं न तो जालसाजी ही कह सका न अप्राकृतिक ही। मैंने कई बार उपर से बड़े बड़े पत्थर गिरते देखे। सारा दिमाग लगाने के बाद भी मुझे मानना पड़ा कि यह मामला भिन्न है। एक परिवार के सभी सदस्य जब घर में प्रवेश करते थे तो चाहे बालक हो अथवा वृद्ध, वे असामान्य हो जाते थे। उनके इलाज के लिये भी मुझे असामान्य प्रयत्न करने पड़े। एक दो ऐसे भी जादू मैंने देखे जिन्हें मैं नहीं समझ सका। मैंने जब भूत दिखाने की चुनौती दी और ओझा लोग भूत चढ़ाने का मंत्र पढ़ने लगे तब जिस पर भूत चढ़ रहा था वह भी उसका षण्यंत्र नहीं था। मैं आज तक नहीं समझा कि उस पर क्या प्रभाव था, और मेरे डाटते ही वह प्रभाव कैसे समाप्त हुआ। किन्तु यह सच है कि प्रभाव था और खत्म भी हुआ। एक भूत प्रभावित व्यक्ति के दोनों कानों में पीपल की लकड़ी सटाकर तथा उसके दोनों हाथों की उंगलियों के बीच लकड़ी लगाकर दबाते ही भूत उतारने का प्रयोग मैंने किया है। वह क्या था और कैसे उतर गया यह कारण और परिणाम मैं आज तक नहीं समझ सका। असामान्य गतिविधि के बच्चों को झाड़-फूक से भी ठीक होते मैंने देखा है, और उन्हीं बच्चों को डाक्टर से भी ठीक होते देखा है। यदि बीमारी थी तो दूर से फूक देने से कई माह के लिये ठीक कैसे हुई यह रहस्य मैं अब तक नहीं सुलझा सका।

लम्बे समय तक पूरे प्रयत्न के बाद भी मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सका कि भूत-प्रेत शारीरिक बीमारी है या मानसिक अथवा कोई प्राकृतिक प्रकोप भी है। अन्त में हार थक कर मैंने रामानुजगंज छोड़ते समय यह निष्कर्ष लिखा कि प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को भूत और सुलझ गये रहस्य विज्ञान कहे जाते हैं। जब तक हसने वाली गैस का शोध नहीं हुआ तब तक वह चमत्कार था और बाद में विज्ञान बन गया। हिस्टीरिया की बीमारी का भी कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है।

संभव है कि आज हम जिन घटनाओं को असमान्य मान रहे हैं वे भविष्य में विज्ञान द्वारा सामान्य प्रमाणित कर दी जावे और हम उन्हें भूत-प्रेत, जादू-टोना, तंत्र-मंत्र की जगह विज्ञान सम्मत घटनाएँ मानने लग जावे किन्तु जब तक विज्ञान प्रमाणित नहीं करता तब तक उन्हें किसी तर्क से असत्य सिद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने रामानुजगंज में जो प्रयोग किया उसके कारण वहाँ के आस पास के लोग भूत प्रेत के नाम पर होने वाले छल कपट और जालसाजी से बच गये। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लग गये कि आपका नाम बजरंग होने के कारण ही हो सकता है कि भूत-प्रेत, तंत्र-मंत्र आपसे डर कर दूर भागता है किन्तु मैं जानता हूँ कि इस कहानी में कोई दम नहीं है। फिर भी इस कथन में कुछ सच्चाई दिखती है कि मेरे द्वारा भूत-प्रेत के अस्तित्व को अस्वीकार करने के कारण मेरा मानसिक मनोबल उंचा है इसलिये मैं इन सबसे प्रभावित नहीं होता। बल्कि टकराकर इनकी पोल खोल देता हूँ। मुझे, मेरे परिवार को तथा मेरे निकट वर्ती मित्रों को यदि भूत प्रेत तंत्र मंत्र न मानने के कारण कोई सुरक्षा मिली हुई है तो फिर क्यों न अन्य लोग भी ऐसा ही प्रयास करें। न मानने वाले मानने वालों की तुलना में अधिक संतुष्ट है। इसलिये मैं समझता हूँ कि इनके अस्तित्व के होने न होने की बहस से दूर रहते हुए इन्हें अस्वीकार कर दिया जाये।

मैं पिछले साठ वर्षों के अनुभव से यह बताने की स्थिति में हूँ कि धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से भूत-प्रेत की घटनाएँ कम हो रही हैं। पिछले दस पंद्रह वर्षों से मैंने रामानुजगंज शहर में पत्थर गिरने की कोई भी घटना नहीं देखी। किसी व्यक्ति को भूत लगे ऐसी घटनाएँ भी बहुत ही कम हो गयी हैं। क्या प्रभाव है और क्यों भूत-प्रेत कम हो रहे हैं। यह समझ पाना मेरे बस की बात नहीं। किन्तु भूत प्रेत के नाम पर आज भी धूर्तों और ठगों का बाजार बंद नहीं हुआ है।

मैं अब तक नहीं कह पा रहा हूँ कि भूत प्रेत का अस्तित्व है या नहीं। किन्तु मेरी एक सलाह अवश्य है कि हम अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भूत-प्रेत, तंत्र-मंत्र के अस्तित्व को बिल्कुल स्वीकार न करें। किन्तु यदि कोई अन्य ऐसा मानता है तो हम उसके समक्ष ऐसा कोई दावा भी न करें कि वह झुठ बोल रहा है अथवा ऐसी घटनाएँ असत्य हैं। क्योंकि असत्य कह देने मात्र से कोई बात असत्य नहीं हो जाती। यदि किसी व्यक्ति को किसी बीमारी का भूत प्रेत से इलाज कराने पर विश्वास हो तो उसे हम समझा सकते हैं कि वह ऐसा न करे और डा० से इलाज करावे। किन्तु हम उसे जोर देकर न कहे अथवा कानून द्वारा उसे रोकने का प्रयास न करें तो अच्छा होगा। कई लोग अंध श्रद्धा उन्मूलन का अच्छा कार्य कर रहे हैं इस तरह वैचारिक धरातल पर इन घटनाओं को चुनौती दी जा सकती है। और दी जानी चाहिये किन्तु तोड़ मरोड़ कर या कुतर्क के माध्यम से मैं भूत प्रेत तंत्र मंत्र को भ्रम सिद्ध करने पर अधिक जोर देने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि विज्ञान निरंतर आगे बढ़कर ऐसे अंध विश्वास की पोल खोलता जाए जिससे हम प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को वैज्ञानिक धरातल पर सुलझाने में सफल हो सके।

मंथन क्रमांक 68

अभिमान, स्वाभिमान, निरभिमान

कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हैं—

1 किसी इकाई का प्रमुख जितना ही अधिक भावनाप्रधान होता है, उस इकाई की असफलता के खतरे उतने ही अधिक बढ़ते जाते हैं। दूसरी ओर जिस इकाई का संचालक जितना ही अधिक विचार प्रधान होता है उस इकाई की सफलता के अवसर उतने ही अधिक होते हैं।

2 भावनाप्रधान व्यक्ति का नेतृत्व अपनी इकाई को नुकसान पहुंचाता है तथा अन्य इकाईयों को लाभ। विचार प्रधान नेतृत्व अपनी इकाई को तो लाभ पहुंचाता है किन्तु अन्य के लिए लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी।

3 भावनाप्रधान नेतृत्व न तो समस्याओं का समाधान कर सकता है न ही समस्याएं बढ़ाता है। विचार प्रधान नेतृत्व ही समस्याओं का विस्तार भी कर सकता है और समाधान भी।

4 चाहे व्यवस्था व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो अथवा सामाजिक। व्यवस्था प्रमुख को हमेशा भावना और बुद्धि के बीच समन्वय करने वाला होना चाहिए।

5 भावनाप्रधान व्यक्ति हमेशा शरीफ होता है और बुद्धिप्रधान आमतौर पर चालाक या धूर्त। बुद्धि और भावना का समन्वय ही समझदारी मानी जाती है।

हम यहाँ मान, अपमान, सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान, निरभिमान जैसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में भी अभिमान स्वाभिमान और निरभिमान मुख्य विषय हैं। मैं जानता हूँ कि विषय पूरी तरह नीरस और अरुचिकर है। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए तो ऐसी व्याख्या करना बहुत ही कठिन है किन्तु मंथन योजना के अंतर्गत यह नीरस और कठिन विषय शामिल है। इसलिए अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार मंथन के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग मेरे पास नहीं है।

चाहे स्वाभिमान हो या निरभिमान और अभिमान, सबका संबंध भावनाओं से ही है। कोई भी बुद्धिप्रधान व्यक्ति इन तीनों मानों से लिप्त नहीं होता क्योंकि व्यक्ति चाहे निरभिमानी हो अथवा स्वाभिमानी किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता, चाहे वह मामला इकाईगत प्रगति से जुड़ा हो अथवा सामाजिक समाधान का। समस्याएं पैदा करने में तो मुख्य रूप से

बुद्धिप्रधान व्यक्ति की ही प्रमुख भूमिका होती है। निरभिमानी की तो समस्याएं पैदा करने में कभी कोई भूमिका होती ही नहीं। अभिमानी व्यक्ति अवश्य कभी कभी समस्याएं पैदा कर लेता है। जो व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता का ठीक ठीक आकलन न करके अपनी क्षमता बहुत अधिक मान लेता है और तदनुसार दूसरों के साथ व्यवहार करता है ऐसे व्यक्ति को अभिमानी माना जाता है। अभिमानी तो हमेशा गलत ही होता है। स्वाभिमानी और निरभिमानी परिस्थितिजन्य अच्छे और गलत हो सकते हैं। जब समाज की परिस्थितियां ठीक हो और प्रत्येक को व्यवस्था के द्वारा न्याय मिलने की पर्याप्त संभावना हो तब व्यक्ति को निरभिमानी होना चाहिए, स्वाभिमानी नहीं। किन्तु जब व्यवस्था ही गड़बड़ हो, न्याय मिलने की संभावना न हो तब व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए क्योंकि ऐसे समय में निरभिमानी समाज के लिए घातक होता है। इस संबंध में एक बात और विचारणीय है कि ब्राम्हण वैश्य तथा श्रमजीवी प्रवृत्ति का व्यक्ति आमतौर पर स्वाभिमानी नहीं हो सकता। क्षत्रिय अर्थात् राजनैतिक सत्ता संघर्ष में लिप्त व्यक्ति या तो स्वाभिमानी होता है या तो अभिमानी। राजनीति से जुड़ा व्यक्ति कभी निरभिमानी हो ही नहीं सकता क्योंकि राजनीति से जुड़ा व्यक्ति विद्वान विचारक व्यवसायी श्रमिक भले ही कुछ भी हो किन्तु मान अपमान सम्मान से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते। ऐसे लोग परिस्थितियों के आधार पर भी समझौता कर लिया करते हैं। कहावत है कि एक कम्बल में चार साधु आराम से पूरी रात गुजार सकते हैं किन्तु एक राज्य में दो राजपुरुष न कभी स्वयं चैन से रहेंगे, न ही दूसरों को रहने देंगे क्योंकि हर मामले में उनका स्वाभिमान या अभिमान आड़े आ जाता है।

मैंने इस संबंध में बहुत विचार किया और पाया कि भारत की वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों में आम लोगों को अपना स्वाभिमान बनाये रखने की आवश्यकता है क्योंकि राजनीति सम्पूर्ण समाज पर हावी हो गई है और राजनेताओं का इसी में हित है कि समाज के अन्य लोग सिर झुकाकर चलने की आदत डाल लें। परिस्थितियां बहुत विकट हैं। किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। अभिमान को कुचलने के लिए कोई निरभिमानी नेतृत्व सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए वर्तमान परिस्थितियां बहुत जटिल हैं और इन जटिल परिस्थितियों में समाज को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए।

मंथन क्रमांक 69

उग्रवाद आतंकवाद और उसका भविष्य

कुछ सर्व स्वीकृत मान्यतायें हैं।

1 उग्रवाद मुख्य रूप से विचार तक सीमित होता है और आतंकवाद क्रिया में बदल जाता है। आतंकवाद को कभी संतुष्ट या सहमत नहीं किया जा सकता। सिर्फ कुचलना ही उसका एकमात्र समाधान है।

2 किसी भी प्रकार की तानाशाही व्यवस्था में उग्रवाद या आतंकवाद कभी नहीं बढ़ता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही उग्रवाद आतंकवाद बढ़ता है।

3 तानाशाही से मुक्ति के लिये उग्रवाद या आतंकवाद का समर्थन भी हो सकता है किन्तु लोकतंत्र में किसी भी प्रकार के उग्रवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता। आतंकवाद के समर्थन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

4 वर्तमान समय में भारत के अधिकांश गांधीवादी किसी न किसी रूप में इस्लामिक या वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद का अप्रत्यक्ष समर्थन करते हैं।

सृष्टि के प्रारंभ से ही सफलता में शक्ति की भूमिका निर्णायक रही है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक शक्तिशाली होता था वह उतना ही अधिक फायदे में रहता था। बाद में व्यक्तिगत शक्ति संगठित शक्ति में बदल गई और समूह की ताकत के बल पर राज्य बनने और बिगड़ने लगे। धीरे-धीरे यह भी स्थिति बदली और अब तो अस्त्र शस्त्र ही वास्तविक शक्ति के आधार बन गये हैं।

प्राचीन समय में शक्ति का प्रयोग या तो राज्य के लिये था या व्यक्तिगत। धर्म के लिये बल प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता था क्योंकि प्राचीन समय में धर्म की परिभाषा संगठन न होकर आचरण से जुड़ी थी। धर्म के साथ हिंसा को सर्वप्रथम जोड़ा इस्लामिक कट्टरपंथियों ने। उन्होंने राजनीति को धर्म के साथ मिला लिया और विस्तार के लिये आंशिक हिंसा को आधार मान लिया। स्वाभाविक ही था कि इस्लाम को अपने द्रुत विस्तार में उसका लाभ मिला। दुनिया में जितनी तीव्र गति से इस्लाम का विस्तार हुआ उतना ही किसी धर्म का नहीं हुआ। धार्मिक इस्लाम का भी नहीं। हिन्दू तो बेचारे इस दौड़ में रहे ही नहीं क्योंकि हिन्दुओं ने कभी धर्म, राजनीति और हिंसा को एक साथ जोड़ कर देखा ही नहीं।

हिंसा की उपयोगिता को इस्लाम के बाद ठीक से समझा साम्यवाद ने। उन्होंने धर्म, राजनीति और हिंसा को एक साथ न मिलाकर गरीबी, राजनीति और हिंसा को एक साथ मिला लिया। स्वाभाविक ही था कि हिंसा और द्वेष की बैशाखी पर सवार होकर साम्यवाद भी बहुत फला फूला। साम्यवाद ने भी बहुत कम समय में जितनी प्रगति की वह अभूतपूर्व और आश्चर्यजनक थी। साम्यवाद ने अर्ध तानाशाही का मार्ग चुना और प्रजातंत्र के साथ डटकर मुकाबला किया। एक बार तो ऐसा लगने लगा था

कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र के स्थान पर साम्यवाद ही साम्यवाद छा जायेगा। भले ही बाद में वे सपने बिखर गये यह अलग बात है किन्तु बल प्रयोग ने साम्यवाद के नाम पर दुनिया में स्वयं को स्थापित तो कर ही लिया था।

ऐसे ही समय में भारत में बल प्रयोग की महत्ता को समझा आर.एस.एस. अर्थात् संघ ने। उसने महसूस किया कि धर्म राजनीति और हिंसा को मिलाकर यदि इस्लाम दुनिया में इतने पैर फैला सकता है तो हिन्दू भारत में क्यों नहीं सफल हो सकता।

हिन्दुत्व के पास भारत में संख्या बल है। समृद्ध विज्ञान है, उज्ज्वल भूतकाल का इतिहास है। उनके पास इस्लामिक उग्रवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का भी अच्छा अवसर उपलब्ध है। इस्लाम के पास तो यह सब नहीं। फिर हमें प्रगति करने में क्या बाधा है। स्वाभाविक ही था कि संघ भी बहुत तेज गति से बढ़ा। बहुत कम समय में ही संघ एक राजनैतिक ताकत बन गया। अपने महत्वपूर्ण विस्तार काल में ही यदि संघ और गांधी हत्या कांड एक साथ नहीं जोड़े गये होते तो संघ का विस्तार किसी के रोकने से रूकने वाला नहीं था किन्तु एक अप्रत्याशित घटना ने संघ को बहुत नुकसान किया। फिर भी संघ ने धीरे धीरे स्वयं को पुनः स्थापित कर लिया और तीन चार वर्ष से तो स्पष्ट आसार दिखने लगे कि संघ भारतीय राजनीति में निर्णायक बढ़त प्राप्त कर चुका है। इस तरह दुनिया में शक्ति के बल पर इस्लाम और साम्यवाद ने स्वयं को स्थापित कर लिया और भारत में संघ ने। कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे की गलती को रोकने के लिये बल प्रयोग करना उचित मानने और करने लगता तब ऐसे बल प्रयोग का औचित्य उग्रवाद में बदलने लगता है। जब तक बल प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित रहता है, तब तक ऐसे समूह को आपराधिक गिरोह तक सीमित माना जाता है किन्तु जब ऐसा बल प्रयोग किसी सिद्धान्त के आधार पर होता है तब वह अपराध न होकर उग्रवाद बन जाता है। हिंसा का औचित्य संगठित होकर उग्रवाद और अनियंत्रित होकर आतंकवाद बन जाता है। उग्रवाद में आमतौर पर विचार प्रसार अधिक होता है और हिंसात्मक सक्रियता कम किन्तु आतंकवाद में विचार प्रचार न होकर सक्रिय हिंसा ही लक्ष्य बन जाती है। तानाशाह देश में उग्रवाद या आतंकवाद न के बराबर होता है। किन्तु तानाशाह देश अपने पड़ोसी देश में हमेशा ही आतंकवाद को प्रश्रय दिया करते हैं। इसलिये यदि किसी देश में तानाशाही है तो तानाशाही से मुक्ति के लिये उग्रवाद या आतंकवाद को एक मार्ग के रूप में माना जा सकता है। किन्तु यदि किसी देश में लोकतंत्र है तो किसी लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के विरुद्ध बल प्रयोग ही अपराध है। उग्रवाद या आतंकवाद का तो किसी भी स्वरूप में औचित्य होता ही नहीं। यदि किसी लोकतांत्रिक देश में राज्य से भिन्न किसी बल प्रयोग का किसी भी रूप में औचित्य सिद्ध करने की बात होती है तो वह सीधा सीधा उग्रवाद है और ऐसी बात का विरोध किया जाना चाहिये।

हिंसा जब सिद्धान्त के रूप में स्थापित होने लगती है और उसे सफलता भी मिलने लगती है। तब उसमें एक दोष शुरू होता है कि उसमें सीमाओं के सारे बंधन टूट जाते हैं। हिंसा उग्रवाद में और उग्रवाद आतंकवाद में बदल जाता है। यह हिंसा का स्वाभाविक दोष है। इस्लाम हिंसा से बढ़कर उग्रवाद में बदला और उग्रवाद से आतंकवाद में। आज से पचास वर्ष पूर्व इस्लाम में हिंसा का स्थान तो था और उसमें कुछ कुछ उग्रवाद भी था किन्तु उसमें आतंकवाद नहीं था। धीरे-धीरे इस्लाम आतंकवाद की दिशा में बढ़ा और फिर उसने आगे बढ़ने की अपेक्षा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साम्यवाद ने भी हिंसा को उग्रवाद में परिवर्तित किया और अफगानिस्तान, चेकास्लोवाकिया, तिब्बत आदि पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। यद्यपि साम्यवाद ने आतंकवाद का स्वरूप ग्रहण नहीं किया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में उग्रवाद या आतंकवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिये किन्तु पूरा भारत पूरी तरह प्रभावित है। भारत एक ओर तो इस्लामिक आतंकवाद से पूरी तरह लहू लुहान है तो दूसरी ओर नक्सलवाद भी उसके लिये निरंतर संकट पैदा किये हुए है। दोनों ही विचार धाराएं गंभीर अपराध हैं क्योंकि नक्सलवाद राज्य सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष तक सीमित है तो इस्लामिक आतंकवाद राज्य सत्ता के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को भी तहस नहस करना चाहता है किन्तु नक्सलवादी आम नागरिकों की हत्या नहीं करते। वे बहुत चुनकर अपना टारगेट तय करते हैं। नक्सलवादियों की कोई घटना ऐसी प्रकाश में नहीं आई है जैसी वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बम्बई बम काण्ड, ब्रिटेन रेल धमाका या बनारस का श्रमजीवी रेल धमाका हो। अपने टारगेट को मारने में यदि निर्दोष मरे तो वे परवाह नहीं करते किन्तु अनावश्यक निर्दोष हत्या से वे बचते हैं। इस संबंध में संघ परिवार की सोच कुछ भिन्न है। इसलिये मेरे विचार में संघ को उग्रवादी तो मान सकते हैं पर आतंकवादी नहीं और इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी कहे जा सकते हैं। नक्सलवाद को घटना अनुसार उग्रवाद या आतंकवाद कह सकते हैं। साथ ही यह भी विचारणीय है कि संघ परिवार का उग्रवाद क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया तक सीमित रहता है जबकि इस्लाम हमेशा ही पहल करता है। इस्लामिक उग्रवाद अपने विस्तार का एक मुख्य माध्यम है तो संघ का उग्रवाद सुरक्षात्मक।

यह सत्य है कि हिंसा त्वरित प्रगति में सहायक होती है किन्तु दूसरी ओर यह भी सही है कि हिंसा आगे बढ़कर उग्रवाद और अंत में आतंकवाद में बदल जाती है और ज्योंही हिंसा का स्वरूप बदलता है त्योंही इसका पतन शुरू हो जाता है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम संकट में है। एक भी ऐसा देश नहीं है जिसकी अब इनके साथ कोई सहानुभूति बची हो। चारों

ओर इस्लाम अविश्वसनीय हो गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सारी दुनिया के समक्ष गिड़गिड़ाते हुए सफाई देनी पड़ रही है। ब्रिटेन के इस्लामिक विद्वानों ने सूझबूझ से काम लिया और आतंकवाद के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया। अमेरिका के इस्लामिक विद्वान पता नहीं क्यों इस सच्चाई को स्वीकार करने में देर कर रहे हैं। इस्लाम के समक्ष अब अस्तित्व का संकट है। या तो कट्टरपंथियों को हिंसा, उग्रवाद और आतंकवाद को सदा सदा के लिये तिलांजलि देनी होगी या इस्लाम स्वयं को समाप्त कर लेगा। अब दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रही है।

साम्यवाद भी संकट में है। साम्यवाद दुनिया के नकशे से तो करीब करीब गायब हो चुका है किन्तु भारत में नक्सलवाद के रूप में उसके अवशेष बचे हैं। केरल, और त्रिपुरा के साम्यवाद को आप साम्यवाद नहीं कह सकते क्योंकि ये साम्यवाद के टिमटिमाते हुए दीपक से अधिक अस्तित्व नहीं रखते। साम्यवाद को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये इस्लाम के कंधे का सहारा लेना ही स्पष्ट करता है कि वह अंतिम चरण में है। नक्सलवाद भी अब निर्णायक दौर में है। छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। वहां से नक्सलवाद हार कर चला गया। बस्तर में भी नक्सलवादियों के पैर उखड़ रहे हैं इसलिये साम्यवाद या नक्सलवाद अब चिंता के विषय नहीं। इस्लामिक आतंकवाद अब भी भारत के लिये चिंता का विषय बना हुआ है। इस्लामिक आतंकवाद से भारत अकेला नहीं निपट सकता क्योंकि पूरे विश्व में इस्लाम की तुलना में हिन्दुत्व की शक्ति कमजोर मानी जाती है दूसरी ओर वैचारिक धरातल पर भी आम हिन्दू मुसलमानों की तुलना में कई गुना अधिक सहजीवन पर विश्वास करने वाला माना जाता है। साथ ही पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ भी उसे चिंतित करता रहता है फिर भी वर्तमान मोदी सरकार बहुत सूझ बूझ और कूटनीतिक तरीके से इस स्थिति से निपट रही है। भारत में संघ परिवार का विस्तार अब तक किसी समस्या के रूप में सामने नहीं आया है। अब तक संघ परिवार ने नरेन्द्र मोदी की लगाम से मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं किया है। मोदी निरंतर शक्तिशाली होते जा रहे हैं। प्रवीण तोगडिया सरीखे उग्रवादी भी बिलो से बाहर आ कर अपने अस्तित्वहीन आक्रमणों की धार कुंद कर चुके हैं। कुछ और भी छिपे हुए उग्रवादी बारी बारी से धराशायी दिखते जायेंगे।

भारत में इस्लामिक आतंकवाद के लिये सबसे बड़ा खतरा तो कांग्रेस पार्टी की सत्तर वर्षों से चली आ रही नीति में आमूलचूल बदलाव दिखता है। यदि कांग्रेस पार्टी और प्रवीण तोगडिया का वर्षों से चला आ रहा अप्रत्यक्ष प्रेम प्रत्यक्ष हो जाता है तो मोदी के लिये अच्छा होगा या बुरा यह विचारणीय प्रश्न नहीं। विचारणीय तो यह है कि फिर इस्लामिक उग्रवाद का भारत में क्या होगा? वैसे ही कांग्रेस पार्टी मुस्लिम उग्रवाद से अपनी दूरी बढ़ाने में प्रयत्न शील है और तोगडिया के बाद तो वह गति और तेज हो सकती है।

आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया के बीच तालमेल बढ़ रहा है। भारत भी उसका प्रमुख भागीदार है। भारत सरकार को इस संबंध में जारी अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं करना चाहिये। आतंकवाद का खात्मा अकेला भारत नहीं कर सकता किन्तु इसका सबसे अधिक लाभ भारत को ही होने वाला है। भारत सरकार को संघ परिवार की नासमझ जल्दवादी से सावधान होकर विश्व आतंकवाद विरोधी योजना के साथ पूरी तरह तालमेल रखना चाहिये।

आतंकवाद से निपटना तो सरकार का विषय है किन्तु उग्रवाद से निपटना तो सरकार का काम नहीं। उग्रवाद से तो समाज ही निपट सकता है। उग्रवाद किसी विचार प्रचार तक सीमित रहता है इसलिये उसे वैचारिक धरातल पर ही चुनौती देनी होगी। किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन आगे बढ़कर उग्रवाद और उसके बाद आतंकवाद का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इसके लिये आवश्यकता है कि हम किसी भी मामले में हिंसा अथवा उग्रवाद के साथ किसी भी रूप में कोई सहभागिता न करें। परिस्थिति अनुसार समर्थन या सहयोग तक सीमित रहा जा सकता है। अभी भारत में संघ परिवार द्वारा इस्लामिक आतंकवाद को कड़ी टक्कर दी जा रही है। इसका अल्पकालिक समर्थन किया जा सकता है। किन्तु उग्रवाद अंततोगत्वा घातक ही होता है। इसलिये हमारा कर्तव्य है कि हम संघ परिवार के भी समर्थन सहयोग के प्रति सतर्क रहे। मैं रामानुजगंज के तोगडिया को भी देख चुका हूँ जिसने अपने ही साथी को हराने के लिये मुसलमान समर्थित कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का पूरा साथ दिया था और आज भी अपने को कट्टर हिन्दू मानता है। इसलिये उग्रवादी तत्वों का कभी भरोसा मत करिये। ये कब किसके शत्रु हो जायेंगे किसके मित्र यह स्पष्ट नहीं। हिन्दुत्व में स्वयं इतनी शक्ति है कि यदि उसे शान्त और निष्पक्ष वातावरण मिले तो वह अपने गुणों के आधार पर ही दुनियां को प्रभावित कर सकता है। आवश्यकता है कि उसे शान्त वातावरण मिले। ऐसा वातावरण बनाने के लिये हमें उग्रवाद को भी निरुत्साहित करना आवश्यक है। उग्रवाद को हिन्दू मुसलमान में विभाजित करने की अपेक्षा उग्रवाद और शान्ति व्यवस्था के बीच बाटने की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति हिंसा का समर्थक है उसे हम किसी भी रूप में समर्थन नहीं कर सकते। हमारा तो उस व्यक्ति के लिये पूरा समर्थन है जो सहजीवन पर विश्वास करता है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान।

यदि दुनियां की राजनैतिक शक्ति योजना बनाकर आतंकवाद मुक्त दुनिया बना दे तथा हम भारत के लोग आपस में मिलकर उग्रवाद मुक्त भारत बना सकें तो यह प्रयास हम सब के लिये स्वर्णिम युग के समान माना जायेगा।

सामयिकी

न्यायपालिका का आपसी विवाद

भारत की न्यायपालिका ने एक नया इतिहास रचा जब सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस की। कुछ लोगों ने इसे लोकतंत्र पर संकट बताया तो कुछ ने इसे सरकार की असफलता। इस संबंध में कुछ बातें स्वयं सिद्ध हैं।

- 1 विरोध करने वाले चार न्यायाधीशों की छवि इमानदार कार्यकुशल और वरिष्ठ के रूप में विख्यात है।
- 2 किसी भी ईकाई के पास जब शक्ति बढ़ने लगती है तब भ्रष्टाचार भी बढ़ना उसका स्वाभाविक परिणाम होता है। जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तब आपसी टकराव भी बढ़ना उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया में शामिल है।
- 3 मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य युद्धरत न्यायाधीशों के बीच कोई सैद्धांतिक टकराव नहीं था, बल्कि सत्ता संघर्ष था जो दीपक मिश्रा जी के मुख्य न्यायाधीश बनते ही जन्म ले चुका था और बढ़ता गया।
- 4 विपक्ष ने इस टकराव को हवा देकर लाभ उठाने का पूरा प्रयास किया। इस प्रयास में चारों न्यायाधीश हथियार के रूप में प्रयुक्त किये गये।
- 5 न्यायाधीशों की प्रेस कान्फ्रेंस ने दो समाधान कर दिये हैं। 1 न्यायिक सक्रियता की समस्या हल हो गई है। 2 विपक्ष के एक बड़े हथियार की हवा निकल गई है।

दुनियां जानती है कि जब से भारत में न्यायिक सक्रियता बढ़नी शुरू हुई है तब से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार भी बढ़ना शुरू हुआ। ज्यों ज्यों न्यायपालिका ने अपनी सर्वोच्चता बढ़ाने का प्रयास किया त्यों त्यों न्याय पालिका में आपसी खींचतान भी बढ़नी शुरू हुई। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि ऐसा प्रायः नहीं देखा जाता है कि कोई एक व्यक्ति किसी पद पर बैठकर पद का दुरुपयोग करते रहे और अन्य लोग समकक्ष होते हुए भी उसका मुंह देखते रहे। यह बात देश भर के सभी विभागों पर एक समान रूप से देखने को मिलती रहती है। यह अवश्य है कि मुंह देखने वाले लोग ऐसे टकराव को कोई सिद्धान्त के आवरण में ढक देने का प्रयास करते हैं। न्यायिक टकराव का मामला भी इससे भिन्न नहीं है। एक ओर तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश समान होते हैं, दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ और कनिष्ठ का भेद होता है। प्रेस कांफ्रेंस करने वाले न्यायाधीश भी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि इन दोनों बातों में से वे किसे सच मानते हैं।

एक जस्टिस लोया का मामला बहुचर्चित है जिसे लेकर राजनीति दो भागों में बंट गई जिसमें विपक्ष तथा चार जजों का एक पक्ष बन गया तथा मुख्य न्यायाधीश एवं सरकार का दूसरा। तीन वर्ष पूर्व अमित शाह के विरुद्ध सोहराबुद्दीन हत्या केश में जिस न्यायाधीश के पास केश चल रहा था उनकी अकस्मात् मृत्यु हो गई थी। अब तीन वर्ष बाद कुछ जागरूक लोगों ने उस मामले की जांच करने के लिये न्यायालय में आवेदन दिया। उक्त आवेदन की जांच जिन जजों को सौंपी गई उन जजों पर अमित शाह विरोधी पक्ष को विश्वास नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्य न्यायाधीश ने जानबुझकर यह मामला ऐसी बेंच को दे दिया दूसरी ओर सत्ता पक्ष का मानना है कि विपक्ष ने जिन जजों को इस मामले के लिये सेट कर रखा था उससे भिन्न जज के पास मामला जाने से उनका षण्यंत्र विफल हो जायेगा। कहा नहीं जा सकता कि सच्चाई क्या है किन्तु इतना स्पष्ट है कि न्यायपालिका में सेट करने का धंधा लम्बे समय से चल रहा है, यह बात स्पष्ट हो गई। कौन किसी को फसाने के लिये जजों का उपयोग कर रहा है या कौन बचने के लिये यह विषय महत्वपूर्ण नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं कि इस घटना से लोकतंत्र को गहरा नुकसान हुआ है। मेरे विचार से ऐसा कहना ही गलत है। जब से न्यायपालिका सर्वोच्च सिद्ध करने की छीना झपटी में शामिल हुई तब से ही न्यायपालिका लोकतंत्र की गिरावट में शामिल हो गई थी। वर्तमान घटनाक्रम तो उसका स्वाभाविक परिणाम मात्र है। जिन चार जजों ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर प्रेस कांफ्रेंस की उनका भी लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सारा मामला व्यक्तिगत टकराव तक सीमित था जिसे सिद्धान्त का आवरण डाल दिया गया है। जिस तरह चार न्यायाधीश विपक्ष और खासकर वामपंथियों के पक्ष में खड़े दिखे उससे स्पष्ट होता है कि इस टकराव में सत्ता संघर्ष भी पूरी तरह शामिल रहा। पिछले तीन वर्षों से दो विचारधाराओं के बीच खुला संघर्ष चल रहा है। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में तथा राजनीति के क्षेत्र में तो टकराव स्पष्ट था ही। बहुतों ने इस टकराव से प्रभावित होकर अपने सम्मान लौटाये थे तो वही युनिवर्सिटीज इस वैचारिक टकराव में शामिल दिखीं। राजनैतिक दल तो इस टकराव के सुत्रधार रहे ही हैं। अब न्यायपालिका भी दो गुटों में बटकर इस टकराव के हथियार के रूप में प्रयोग में आयी। लगता है कि दोनों पक्षों के बीच टकराव का यह अंतिम रणक्षेत्र है। न्यायपालिका को इस क्षेत्र से बचना चाहिये था। किन्तु कहावत है कि युद्ध से तो परिवार बच जाये किन्तु मंथरा बचने दे तब न। अंत में मेरा यह मत है कि यह टकराव किसी भी रूप में कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। चार न्यायाधीशों ने जिस कदम को हाईड्रोजन बम समझ रखा था वह

फुस हो जाने से लोकतंत्र का कोई नुसकान नहीं हुआ है। यदि न्यायपालिका अपने पास शक्ति संग्रह की भूख से बच जाये तो ये सारे टकराव भी अपने आप समाप्त हो जायेगे और भ्रष्टाचार की भी चर्चा अपने आप खत्म हो जायेगी। लोकतंत्र अपनी तीन समकक्ष इकाइयों में से किसी एक के शक्तिशाली होने से खतरे में आता है। ऐसा लगता है कि उस खतरे पर विराम लग गया है।

प्रश्नोत्तर

श्री सिंघला जी अजमेर राजस्थान

ज्ञानतत्व का अंक 364 मिला। इस बार समग्र रूप से किन्तु सूक्ष्म में विचार प्रस्तुत है। पृष्ठ-1 विचार-लोक स्वराज्य आदर्श स्थिति होती है। प्रश्न- लोक स्वराज्य क्या है? इसके किसी ऐतिहासिक स्वरूप का उदाहरण दे सकेंगे?

पृष्ठ 2 विचार- गैरकानूनी और अनैतिक को भी। प्रश्न-अनावश्यक कानून बनाकर साधारण जनता पर भी अपराधी होने का लेबुल लगाकर वाहवाही लूटना इतराना ही कहा जाना चाहिये। इस जद में वे स्वयं भी आते तो है किन्तु वी आई पी होकर बच निकलते है। क्या यह सही है।

पृष्ठ 2 विचार- मद 10 सुरक्षा और न्याय की जगह। प्रश्न- 'क्योंकि इसमें दायित्व नगण्य और मलाई अधिक है। चुनाव में पानी की तरह पैसा वैसा ही नहीं बहाया जाता। मेरी सहमति है।

पृष्ठ 6 विचार- नाथूराम गोडसे एक उग्रवादी विचारों से संचालित व्यक्ति था। फांसी पर चढ़ना पडा। प्रश्न- यदि आप गांधी वध क्यों पुस्तक पढ लेंगे तो निश्चय मानिये आपके विचार अन्यथा प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। आपके विचार पढकर मुझे यू पी की मुख्य मंत्री रहीं मायावती की याद आ गई। उन्होंने देश के लिये अपनी जीवन बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी कह दिया था और उस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वस्तुतः आतंक वह है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। हिटलर ने यहूदियों की बड़ी संख्या में निर्मम हत्याएँ की। उसका उसके पीछे केवल उनसे घृणा करना कारण था। इसी प्रकार आज का मुस्लिम आतंकवाद है। क्या उसका कोई तर्कपूर्ण उद्देश्य है?

इसी क्रम में आपने हिन्दू आतंकवाद की बात करते हुए कहा कि हिन्दू आतंकवाद का खतरा पूरी तरह समाप्त हो गया है। आपकी यह बात सही नहीं है और समझ से परे है। हिन्दू आतंकवाद पर कुछ प्रकाश डाल सके तो अच्छा होगा।

गांधी वध क्यों पुस्तक से दो उद्धरण--

क- मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि उस दिन के श्रोतागणों को जूरी बनाकर गोडसे की अपील का निर्णय करने को कहा जाता तो वह भारी बहुमत से निरपराध घोषित होता। जस्टिस खोसला

ख- यदि देश भक्ति पाप है तो मैं मानता हूँ मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आपको उस प्रशंसा का अधिकारी मानता हूँ। मुझे विश्वास है कि मानव द्वारा स्थापित न्यायालय के उपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जायेगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिये यह काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिन्दुओं पर घोर संकट आये हिन्दू नष्ट हुए। नाथू राम गोडसे

पृष्ठ 27 विचार- जस्टिस भगवती ने जनहित याचिकाओं को चुनने का जो असंवैधानिक अधिकार।

प्रश्न- 'याचिका सुनने का अधिकार असंवैधानिक कैसे माना? आगे आपने लिखा है कि न्यायपालिका दुरुपयोग करने लगी.....' यह कैसे? इसे कृपया स्पष्ट करे।

आपने लिखा है कि तानाशाही में जिन्दगी को छीनने के अवसर ही नहीं मिलते। यह बात समझ में नहीं आयी। पृष्ठ 29 दलितों की परिभाषा की चर्चा है। किसी काम को करने के लिये योजना बनानी होती है। बड़े काम को अंजाम देने के लिये समस्याओं को विभाजित यानी उसका विश्लेषण करना होता है। इसी विचार को लेकर भारत में वर्ण व्यवस्था को स्वरूप प्रदान किया गया था। किसी भी व्यवस्था के चलते चलते उसमें दोष आने लगते हैं यह स्वाभाविक है। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। ऐसे में वर्ण व्यवस्था में जो दोष आये उन्हें दूर करने की आवश्यकता थी। इसके विपरीत लोकतांत्रिक राजनीति ने उस सामाजिक व्यवस्था को रद्दी की टोकरी में डाल कर नाना विभाग तैयार कर व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। यदि आम जन ही ऐसी समस्याओं को सुलझा ले तब मनीषियों की क्या आवश्यकता है। उसकी क्या अहमियत है। इसके विपरीत आज के लोकतंत्र में अयोग्य को ही जगह है। अयोग्य को ही सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है किन्तु वह भी यह नहीं कहता कि उसे दूसरे का हक छीन कर दो। दूसरे का हक छीन कर देना अल्पकालीन सत्तासीन रहने वाले लोगों की ओछी नीति ही हो सकती है।

महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता किसने कब और क्यों कहा? इसकी क्या कोई सार्थकता है। हो सके तो प्रकाश डाले। राजनीति शास्त्र के अनुसार देश एक भूखंड होता है। उसे राष्ट्र बनने या कहलाने के लिये उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिये। वे विशेषताएं राष्ट्र के तत्व कहे जाते हैं। उनके होते देश राष्ट्र कहलाता है। नेहरू इस सोच से सहमत नहीं थे।

भ्रूण हत्या विषयक आपका चिंतन सही है।

आपने प्रधान मंत्री मोदी जी की पर्याप्त प्रशंसा करते हुए संघ परिवार को कुछ नसीहत दी है, संदेश दिया है। यह इतिहास है और अटल सत्य है कि मोदी और संघ परिवार एक दूसरे के पूरक हैं। इस दृष्टि से उनके विषय में टिप्पणी करना या सुझाव देने जैसी भावना क्या अनावश्यक प्रतीत नहीं होती। यह भावना संघ फोबिया का स्वरूप प्रस्तुत करती है।

उत्तर—मेरे विचार में लोक स्वराज्य वह स्थिति होती है जिसमें राज्य सुरक्षा और न्याय तक सीमित रहकर परिवार या समाज की अपनी आंतरिक व्यवस्था में कोई दखल नहीं देता। लोक स्वराज्य की भूमिका जनकल्याणकारी राज्य की न होकर जनकल्याणकारी समाज के सहायक की होती है। जन कल्याण समाज का कार्य होता है राज्य का नहीं। जो राज्य सुरक्षा और न्याय भी न दे सके और जनकल्याण का नाटक करते रहे ऐसे राज्य को एक क्षण भी स्वीकार नहीं करना चाहिये।

गोडसे की अन्ध राष्ट्र भक्ति पर मुझे न पहले संदेह था न अब है। गोडसे जिस विचार धारा से प्रभावित था वह विचारधारा दोषी थी जिससे प्रभावित होकर गोडसे ने राष्ट्रभक्ति का गलत अर्थ समझ लिया। यदि वह गांधी के सम्पर्क में रहा होता तो वह नेहरू पटेल की तुलना में अधिक बड़ चढ़ कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेता और देश को स्वतंत्रता के बाद गांधी विचारों से ओत प्रोत गोडसे का नेतृत्व मिला होता। अर्थात् हम लोग गांधी के नाम का दुरुपयोग करके गांधी विचारों की हत्या करने वाले नेहरू अम्बेडकर पटेल आदि से बच जाते। किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य था कि गोडसे गांधी को बदले गांधी विरोधी विचारधारा वालों के प्रभाव में आ गया और उसने देश भक्ति की गलत परिभाषा समझ ली। देशभक्ति का अर्थ कानून को ठीक कराने से लिया जाना चाहिये। कानून तोड़ने से नहीं। यदि कानून तोड़ना ही देश भक्ति की कोई परिभाषा है तो नक्सलवादी देशभक्त हैं या नहीं इसपर भी विचार करना होगा। स्पष्ट है कि मैं लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोधी हूँ, चाहे वह हिंसा देश भक्ति के लिये ही क्यों न की गई हो।

मेरे विचार में भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका और न्यायपालिका की सीमाएं स्पष्ट हैं। न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करने के लिये बाध्य है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि न्यायपालिका जनहित को परिभाषित नहीं कर सकती। सिर्फ विधायिका ही कर सकती है। किन्तु विधायिका ने सन पचास से ही असंवैधानिक तरीके से न्यायपालिका और कार्यपालिका को कमजोर करना शुरू कर दिया था। इसलिये न्यायपालिका द्वारा जनहित याचिकाएं सुनने के असंवैधानिक कार्य को भी आज तक चुनौती नहीं मिली। न्यायपालिका और विधायिका के बीच सर्वोच्चता का टकराव बहुत घातक है। आज हम सत्तर वर्षों से इस टकराव के दुष्परिणाम देख रहे हैं। वर्तमान समय में भी यह टकराव खतम होता नहीं दिख रहा।

न्यायपालिका के विकेंद्रीयकरण से मेरा स्पष्ट आशय यह है कि न्यायपालिका स्वयं को जनहित याचिकाओं से दूर कर ले। न्यायालयों को प्रशासनिक या कार्यपालिक आदेश न देकर सिर्फ न्यायिक आदेश तक सीमित कर लेना चाहिये। न्यायपालिका को चाहिये कि वह अपराध गैर कानूनी तथा अनैतिक के अंतर को समझे और तदनुसार अपनी प्राथमिकता बनावे। आपराधिक मुकदमों को प्राथमिकता दे तथा गैर कानूनी अनैतिक को समय मिलने पर निपटाने के लिये टाल दे।

जहां तक मोदी जी और संघ की चर्चा है तो मैं संघ और मोदी को एक दूसरे का पूरक नहीं मानता। मैं कभी संघ का प्रशंसक नहीं रहा। मेरे विचार में संघ परिवार कभी भी स्वतंत्र शासन व्यवस्था का पक्षधर नहीं रहा। संघ चाहता है कि जो भी व्यक्ति सत्ता में आवे वह उसी तरह का हो जिस तरह सोनियां गांधी की कठपुतली मनमोहन सिंह रहे। ऐसा कठपुतली प्रधानमंत्री न अटल जी रह सके न ही नरेन्द्र मोदी रह पायेंगे। अभी तो प्रवीण तोगडिया से शुरुआत हुई है। इस संबंध में इसी अंक में आतंकवाद विषय पर व्यापक चर्चा हुई है।

उत्तरार्ध द्वारा नवीन शर्मा

पुरातन काल में भारत विचारों एवं धन सम्पदा, दोनों ही मामलों में काफी धनी था। भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने विचारों से विश्व स्तर पर भारत का मान बढ़ाया। विगत दो तीन हजार वर्षों में भारत इन दो स्तरों पर काफी कमजोर हुआ है। ऐसा होने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण राजनीति धर्म समाज जैसे सभी क्षेत्रों का व्यवसायीकरण हो जाना और फिर व्यवसायीकरण का राजनीतिकरण हो जाना। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों में नैतिक पतन के रूप में दिखाई पड़ा। नैतिक पतन ही वजह है कि भारत में अपराध एवं भ्रष्टाचार की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लूट, चोरी, हत्या व बलत्कार जैसे अपराध तो अब सामान्य सी घटनाएं लगने लगीं हैं। यह बात बजरंग मुनि जी ने विचार मंथन की जनवरी माह की बैठक में व्यक्त किये। मुनि जी ने आगे बोलते हुये कहा कि भारत में अपराध की अत्यधिक

समस्याएं राज्यों की असक्रियता के वजह से हैं। अगर राज्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से करे और आपराधिक समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करे तो आपराधिक समस्याओं के साथ साथ भ्रष्टाचार और चरित्र हनन की समस्याएं भी स्वतः समाप्त हो जाएंगी।

आर्थिक तौर पर भारत में दो समस्याएं मुख्य रूप से हावी हैं। पहली समस्या असमान आय स्तर है तो दूसरी समस्या श्रम शोषण की है। असमान आय स्तर की स्थिति आजादी के बाद से ही लगभग वही बनी हुयी है। देश के लगभग 90 प्रतिशत संसाधनों पर कुछ ही लोगो का हक है। वही लोग निर्धारित करते हैं भारत की आर्थिक नीतियां किस प्रकार कार्य करेंगी। इस वजह से गरीब और गरीब और अमीर और अमीर होता चला गया। यही कारण है कि देश के गरीबों में व्यवस्था के प्रति काफी गुस्सा है। दूसरी समस्या श्रम शोषण की है। मेहनतकशों को उनके श्रम के मुताबिक मेहनताना नहीं मिल पाता है।

सरकार दुनिया को यह दिखाती फिरती है कि अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन आंतरिक तौर पर स्थितियां बिल्कुल उसके उलट है। भारत अभी भी आयात व निर्यात के क्षेत्र में असन्तुलन, किसानों की आत्महत्या, अत्याधिक विदेशी कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण भारत सरकार की गलत अर्थनीति है। अगर भारत अपनी अर्थनीति में सुधार करे एवं अर्थव्यवस्था को खोल दे और पूर्ण रूप से उसे बाजार पर निर्भर कर दे तो अनेक आर्थिक समस्याओं का निवारण बाजार खुद ब खुद कर लेगा। बाजार के स्वतंत्र होने से छोटे मझोले किसान कामगार खुद अपने आय के स्तर में सुधार कर लेंगे। इससे बेरोजगारी के स्तर में भी कमी आएगी और युवाओं को रोजगार का अवसर बाजार द्वारा ही प्राप्त हो जायेगा।

बजरंग मुनि जी ने आगे कहा कि आज दुनिया में नित नए नए अविष्कार हो रहे हैं। यहां तक कि कृत्रिम मानवों का भी अविष्कार हो चुका है। रोज नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं और उनका इलाज भी खोजा जा रहा है। विश्व जितनी तेजी से विज्ञान की ओर अग्रसर है उतनी ही तेजी से नैतिक एवं सामजिक पतन की तरफ भी बढ़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में नैतिक पतन पर गौर करें तो पाते हैं कि आजकल छोटी छोटी बच्चियों तक से बलात्कार हो जाता है। भाई भाई को मार देता है। यह सब नैतिक पतन का ही परिणाम है। सामजिक पतन के रूप में जन्म आधारित वर्ण और जाति व्यवस्था भारत में व्याप्त सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। इन चीजों में तभी सुधार लाया जा सकता है जब हम घर में अपने बच्चों को अच्छी नैतिक एवं सामजिक शिक्षा प्रदान करें। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में स्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं।

मुनि जी ने इस बात को और स्पष्ट करते हुये कहा कि धर्म और संस्कृति के आधार पर भी भारत में समस्याएं व्याप्त हैं। धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है और संस्कृति का अर्थ कुछ कार्यों को बिना बिचारे बार बार करना। धीरे धीरे वह आदत में शुमार हो जाती है। उन कार्यों को हम संस्कृति का नाम दे देते हैं। अक्सर लोग धर्म को पूजा पद्धति से जोड़ लेते हैं परन्तु यह ऐसा नहीं। आज कई संस्थाएं खुद को धर्म घोषित कर दी हैं और धर्म एवं संस्कृति के नाम पर देश भर में माहौल को दूषित करने का कार्य कर रही हैं। धर्म एवं संस्कृति का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है।

इस बार की मासिक बैठक में बजरंग मुनि जी ने संविधान को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखते हुये कहा कि भारतीय संविधान में व्याप्त समस्याओं को देखने के लिए हम संविधान का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि भारतीय संविधान अन्य देशों की नकल है। जिस देश का लोकतंत्र ही गुलाम हो उसमें कितनी समस्याएं होंगी।

भारतीय संविधान में जो समानता का तत्व निहित है वह पूरी तरह से छलावा मालूम पड़ता है क्योंकि आर्थिक और क्षमता के स्तर पर दो व्यक्ति कभी एक समान नहीं हो सकते। वर्तमान परिदृश्य में भारत अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है जिन्हें सुलझाना अति आवश्यक है।